अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में हाल ही में शुरू प्रमुख 'ई-गवर्नेंस' सेवाएँ
2.	राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ नियम – 2026
3.	29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2026 : जयपुर
4.	सहकार सप्ताह के अंतर्गत 'राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह'
5.	'मसूदा' से 'वीबीजी राम जी योजना' का राज्य स्तरीय शुभारंभ
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान का दूसरा बूथलेस टोल प्लाजा : मनोहरपुर टोल
7.	आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)
8.	विजय रोडमैप
9.	अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और एपीएएआर
10.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
11.	MECON लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा
12.	जलवायु परिवर्तन बिंदु
13.	हिमालयी रे-फिन मछली

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में हाल ही में शुरू प्रमुख 'ई-गवर्नेंस' सेवाएँ

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 जुलाई, 2026 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के तहत 'राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन', स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच 'स्मार्ट राजस्थान परियोजना', 'राजस्थान इनोवेशन चैलेंज' और 'ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा' का शुभारंभ किया।

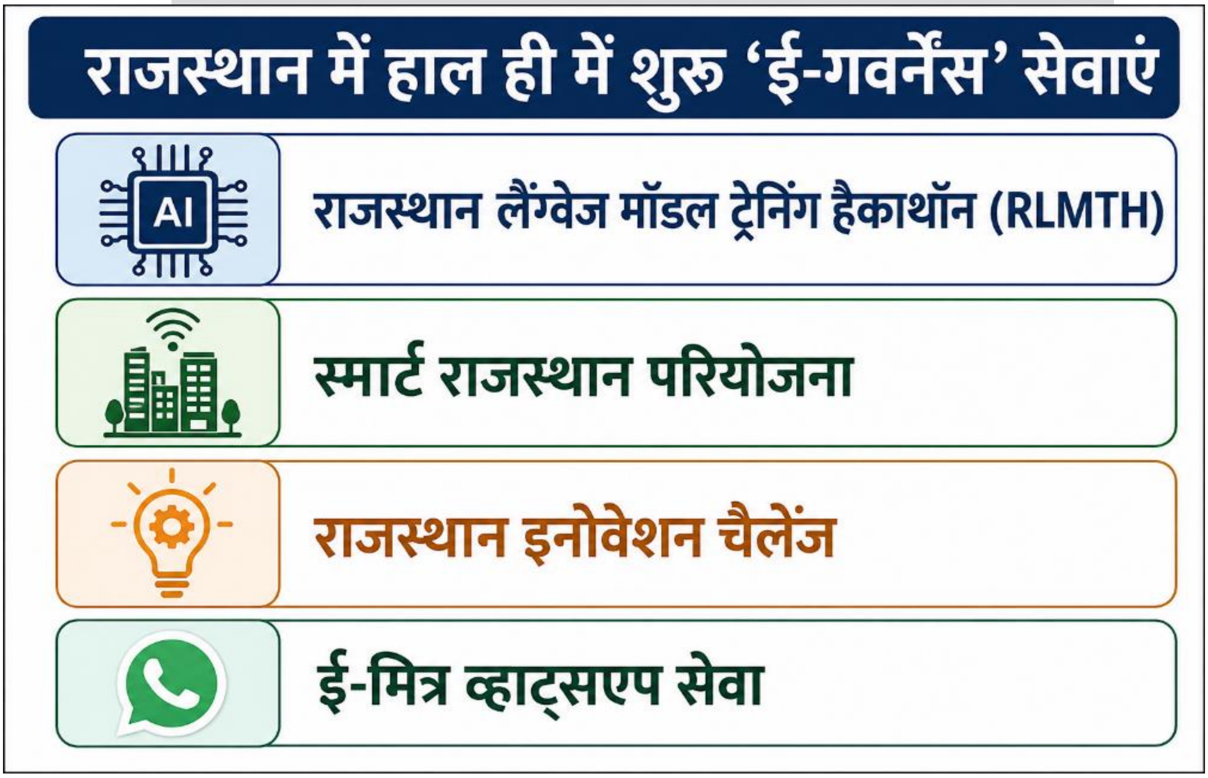

मुख्य बिन्दु:

- **राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन (RLMTH) :** केंद्र सरकार के AI-संचालित प्लेटफॉर्म 'भाषिणी' (BHASHINI) के सहयोग से इस हैकाथॉन की शुरुआत की गई है।

- **उद्देश्य :** राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के लिए AI मॉडल्स को मजबूत और सटीक बनाना।
- **स्मार्ट राजस्थान परियोजना :** यह एक अत्याधुनिक स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच है।
- **उद्देश्य :** सरकारी डेटाबेस का उपयोग करके नागरिकों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे और तीव्र सेवाएँ प्रदान करना।
- **राजस्थान इनोवेशन चैलेंज :** आईस्टार्ट (iSTART) राजस्थान के माध्यम से शुरू किए गए इस चैलेंज का उद्देश्य राज्य भर में प्रमुख शासन और नागरिक-केंद्रित चुनौतियों का समाधान करने वाले नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की पहचान करना, उनका समर्थन करना और उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाना है।
- इस चैलेंज में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में चिह्नित समस्याओं के लिए स्केलेबल, प्रभावशाली और लागू करने योग्य समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जहाँ इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
  - **प्रथम पुरस्कार :** ₹5 करोड़ तक।
  - **द्वितीय पुरस्कार :** ₹1 करोड़ तक।
  - **तृतीय पुरस्कार :** प्रत्येक के लिए ₹50 लाख तक।
- **ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा :** यह आम जनता के लिए घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने की एक क्रांतिकारी पहल है। प्रदेश के नागरिक इसके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 94610-62705 पर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
- ई-मित्र (e-Mitra) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ई-गवर्नेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को 900 से अधिक सरकारी और निजी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं।
- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर काम करता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में CSC (Common Services Centres) और शहरी क्षेत्रों में ई-मित्र कियोस्क संचालित किए जाते हैं।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान में 79,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्कों के माध्यम से 900 से अधिक सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ नियम – 2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ नियम – 2026' को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई।

मुख्य बिन्दु:

- **नियमों का मुख्य उद्देश्य :** राज्य में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा, वेंटिलेशन, बिजली की व्यवस्था, सेनिटेशन, प्राथमिक चिकित्सा और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नाइट शिफ्ट सुनिश्चित करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- इन नियमों के तहत सभी कारखानों, निर्माण स्थलों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिजिटल और ऑटो-रिन्यूअल (Auto-renewal) आधारित कर दिया गया है।
- **महिला सशक्तीकरण :** महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी है। यद्यपि नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और उनके आने-जाने की सुरक्षित व्यवस्था करनी होंगी।
- **डिजिटलीकरण :** नए नियमों के तहत कारखानों, निर्माण कार्यों, मोटर परिवहन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। सभी प्रकार के आवेदन और फीस का भुगतान आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही हो सकेगा।
- **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रावधान :** नए नियमों में अनुबंध श्रम और अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। कार्य के घंटे, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और सभी प्रकार के रजिस्टरों व रिटर्न के रख-रखाव को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। नियोक्ताओं को अन्य राज्यों से आकर राजस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाएँ और यात्रा भत्ता देना होगा।
- **ओवरटाइम के लिए प्रावधान :** यदि कोई कर्मचारी तय कार्य घंटों (सामान्यत: 8 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह) से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम के हर घंटे के लिए उसकी सामान्य मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान करना होगा।
- **आवश्यक स्वास्थ्य जाँच :** सभी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की वर्ष में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जाँच करानी आवश्यक होगी। साथ ही, कारखानों और निर्माण स्थलों पर अनिवार्य रूप से सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा और योग्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- गंभीर दुर्घटना या खतरनाक घटना की स्थिति में तय समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।

29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2026 : जयपुर

चर्चा में क्यों?

- जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 1 और 2 जुलाई, 2026 को 29वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) आयोजित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजक :** प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से।
- **विषयवस्तु :** विकसित भारत@2047 : AI एनेबल्ड, डेटा ड्रिवेन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेन्स' (Viksit Bharat 2047 : AI Enabled, Data-Driven and Secure Digital Governance)
- **नॉलेज पार्टनर :** नैस्कॉम एवं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), जयपुर।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **जयपुर डिक्लेरेशन (Jaipur Declaration) :** सम्मेलन के समापन सत्र में 'जयपुर डिक्लेरेशन' को अपनाया गया, जो 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों के अनुकूल, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन पर केंद्रित है।
- **सम्मेलन के प्रमुख सेशन :** 'AI बेस्ड गवर्नेन्स फॉर ऑल', 'ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड - वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस इन इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज', 'ड्राइविंग अर्बन— ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी', 'AI फॉर स्मार्ट पुलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी', 'सिटिजन सेंट्रीक गवर्नेंस: इन्क्लुसिव गवर्नेंस' और 'डिजिटल इंटरवेंशंस टू एनहांस एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन'।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार - 2026 : (उत्कृष्ट नवाचार के लिए कुल 17 सम्मान)

- सम्मेलन के दौरान 07 श्रेणियों में कुल 17 उत्कृष्ट परियोजनाओं एवं पहलों को सम्मानित किया गया, जिनमें 10 स्वर्ण, 6 रजत तथा 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।
- **प्रदानकर्ता :** केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह।

स्वर्ण पुरस्कार:

क्र. सं.	संस्था/विभाग	परियोजना/सेवा
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	एग्री स्टैक।
2.	उपभोक्ता मामले मंत्रालय	ई-जागृति।
3.	प्रयागराज मेला प्राधिकरण	महाकुंभ-2025
4.	केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद (K-DISC)	ब्लड बैग ट्रेसिबिलिटी एवं नागरिक संपर्क पोर्टल।
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा में AI-सक्षम नैदानिक निर्णय सहायता प्रणाली।
6.	केरल उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली (DCMS)
7.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)	ICMR-MINDS अध्ययन।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

8.	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ISRO), अहमदाबाद	खतरे की जानकारी एवं DNS फिल्टरिंग सेवा के लिए सुरक्षा उत्पाद।
9.	शहरी विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश	ई-नगरपालिका में साइबर सुरक्षा व्यवस्था।
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	सुदृढ़ डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम।

रजत पुरस्कार:

क्रम सं.	संस्था/विभाग	परियोजना/सेवा
1.	स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद नंदुरबार, महाराष्ट्र	ई-आरोग्य धमनी
2.	पुणे 360	-
3.	काडेपुर ग्राम पंचायत, सांगली, महाराष्ट्र	-
4.	विजय नगर ग्राम पंचायत, पश्चिम त्रिपुरा	-
5.	महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट, उज्जैन	त्रिनेत्र: AI आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली
6.	पंचायती राज मंत्रालय	पंचायत उन्नति सूचकांक

जूरी पुरस्कार:

क्रम सं.	संस्था/विभाग	परियोजना/सेवा
1.	सर्वे ऑफ इंडिया	CORS नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय में सटीक स्थिति निर्धारण सेवाएँ

सहकार सप्ताह के अंतर्गत 'राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह'

चर्चा में क्यों?

- सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 05 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र व्यापी 'सहकार सप्ताह' का आयोजन 29 जून से 06 जुलाई, 2026 तक किया जा रहा है।
- इसी क्रम में 02 जुलाई, 2026 को जयपुर के अपेक्स बैंक में 'राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **सहकारिता मंत्रालय की स्थापना :** केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई, 2021 को एक पृथक मंत्रालय के रूप में।
- **मुख्य उद्देश्य :** "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करना और देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना।
- अमित शाह भारत के पहले और वर्तमान सहकारिता मंत्री हैं।

राजस्थान में सहकारी आंदोलन:

- राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में अजमेर से हुई।
- **वर्ष 1904 :** ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 'सहकारी ऋण समिति अधिनियम' पारित किया गया। तत्पश्चात 25 अक्टूबर, 1905 को भिनाय (अजमेर) में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई।
- **वर्ष 1904 :** डीग में राज्य के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई।
- **वर्ष 1910 :** अजमेर में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की शुरुआत।

सहकारिता से संबंधित राजस्थान के प्रमुख संस्थान:

संस्थान का नाम	स्थापना	मुख्यालय
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	1953	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफैड)	1957	जयपुर
राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ (तिलम संघ)	1990	जयपुर
राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान (RICEM)	1990	जयपुर
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (RCDF)	1977	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर (कॉनफेड)	1967	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	1957	जयपुर

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

‘मसूदा’ से ‘वीबी जी राम जी योजना’ का राज्य स्तरीय शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 जुलाई, 2026 को ब्यावर जिले के मसूदा से 'वीबी जी राम जी (VB-G RAM G) योजना' का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया।

मुख्य बिन्दु:

- **VB-G RAM G :** विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)।
- यह योजना देश में ‘महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)’ के स्थान पर लागू की गई है।
- **राष्ट्रीय शुभारंभ :** आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले के मुक्कावरिपल्ली गाँव से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा।

योजना के मुख्य प्रावधान:

- **रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी :** इस योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी कार्य करवाए जा सकेंगे।
- **कार्य विराम की सुविधा :** फसलों की बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर 60 दिनों का कार्य विराम घोषित किया जा सकेगा।
- **पारदर्शिता :** सभी श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। योजना के सफल कार्यान्वय के लिए जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और AI जैसी तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
- **बजट प्रावधान :** राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत ₹12,636 करोड़ का बजट आवंटित किया है। जो कि राज्य में इस योजना का अब तक का सबसे अधिक बजट है।
- **भुगतान अवधि :** इस योजना के तहत हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो सप्ताह से अधिक की देरी पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। वहीं, प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके।
- **रोज़गार की अनिवार्यता :** किसी भी मजदूर द्वारा काम माँगने पर 15 दिन के भीतर उसे रोज़गार देना अनिवार्य होगा और यदि निर्धारित समय में काम नहीं दिया गया तो संबंधित मजदूर को बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा।
- **सभी राज्यों के लिए न्यूनतम आधार मजदूरी :** ₹300 प्रतिदिन।

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**राजस्थान का दूसरा बूथलेस टोल प्लाजा : मनोहरपुर टोल** ■ हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) - 48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर स्थित मनोहरपुर टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) आधारित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। ■ इसी के साथ यह 'दौलतपुरा टोल प्लाजा' के बाद राजस्थान में शुरू होने वाली अपनी तरह की दूसरी MLFF टोलिंग प्रणाली है। उल्लेखनीय है कि जून, 2026 में 'दौलतपुरा टोल प्लाजा' MLFF प्रणाली को लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम टोल प्लाज़ा है। ■ **प्रणाली के बारे में :** MLFF (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) एक आधुनिक, बाधा-मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम है, जो टोल बूथों की आवश्यकता को समाप्त करता है। RFID रीडर, AI और ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से लैस ओवरहेड गैन्ट्री का उपयोग करके, यह FASTag से टोल राशि स्वचालित रूप से काट लेता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)

चर्चा में क्यों?

- अपनी 90वीं वर्षगांठ के समारोह के हिस्से के रूप में और 2027 में भारत में रेडियो प्रसारण की शताब्दी की तैयारियों के मद्देनजर, आकाशवाणी ने 'स्वर प्रेरणा वीथिका' का उद्घाटन किया ।

मुख्य बिन्दु:

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)

- आकाशवाणी (आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो) भारत का प्रमुख राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। प्रसार भारती के दो मुख्य अंगों में से एक के रूप में कार्यरत है।

स्थापना वर्ष:

- **औपचारिक शुभारंभ:** 1 अप्रैल, 1930 को प्रायोगिक भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में शुरू होने के बाद, 8 जून, 1936 को इसे आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर) नाम दिया गया।
- **नाम “आकाशवाणी”:** इसे औपचारिक रूप से 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के आधिकारिक ऑन-एयर नाम के रूप में अपनाया गया था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1938 में कोलकाता के शॉर्टवेव प्रसारण के उद्घाटन के लिए लिखी गई एक बंगाली कविता से लिया गया है।

MCQ

Q. 'आकाशवाणी' (ऑल इंडिया रेडियो) के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से वर्ष 1930 में प्रायोगिक भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी।
2. वर्ष 1936 में इसे आधिकारिक तौर पर 'अखिल भारतीय रेडियो' (All India Radio - AIR) नाम दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

CIVIL SERVICES

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विजय रोडमैप

चर्चा में क्यों?

- सेना के 31वें प्रमुख (सीओएएस) जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के लिए एक महत्वाकांक्षी, उच्च-तकनीकी परिवर्तन योजना का अनावरण किया, जिसे "विजय" रोडमैप नाम दिया गया है ।

मुख्य बिन्दु:

विजय रोडमैप

- “विजय” रोडमैप भारतीय सेना की युद्ध प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया एक व्यापक रणनीतिक और परिचालन सिद्धांत है।
- यह रोडमैप रक्षा मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है।"परिवर्तन का दशक" (2023-2032) के तहत, सेना को पारंपरिक, एकल-क्षेत्रीय युद्ध रणनीति से हटाकर एक अत्यधिक डिजिटल, संयुक्त-हथियार युद्ध ढांचे की ओर ले जाया जाएगा।
- सेना प्रमुख (सीओएएस) के निर्देशन में विकसित और सभी परिचालन कमानों में कार्यान्वित।

उद्देश्य:

- एक ऐसी तकनीकी रूप से कुशल सेना का निर्माण करना जो पारंपरिक, हाइब्रिड, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वातावरण में लड़ने में सक्षम हो।
- सैन्य संरचना को तेज करने, पुरानी तकनीक को आधुनिक सैन्य उपकरणों से बदलने और परिचालन क्षमताओं को उभरते खतरों के अनुरूप बनाने के लिए।
- "स्वदेशी समाधानों के साथ अपने युद्धों को जीतना" के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को तोड़ना।

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और एपीएएआर

चर्चा में क्यों?

- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विनियमित है।

मुख्य बिन्दु:

- APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी एक अद्वितीय 12-अंकीय छात्र पहचान संख्या है जो ABC प्रणाली से जुड़ी होती है।
- इसे "एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी" पहल के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, और यह प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक एकल शैक्षणिक पहचान बनाता है।

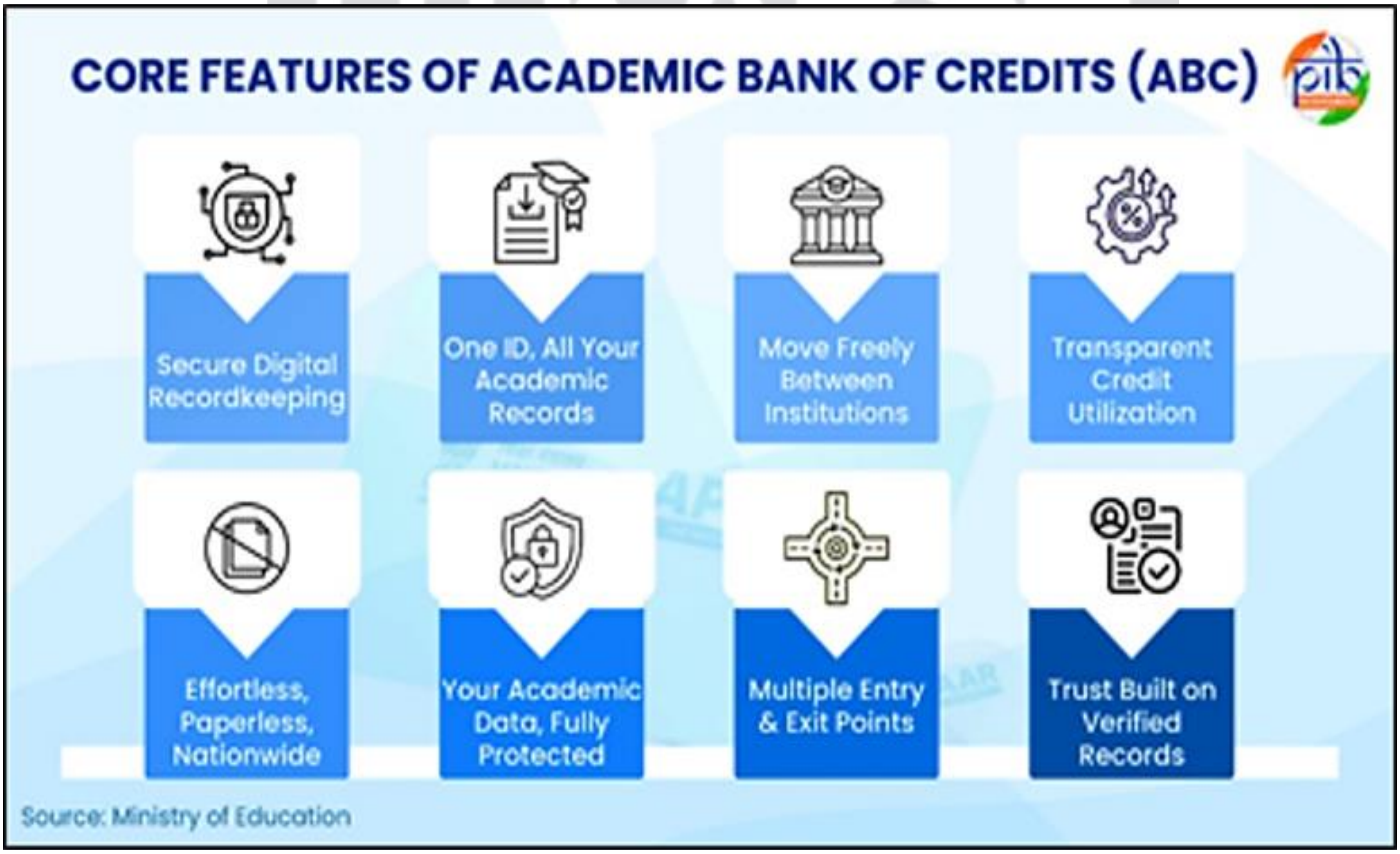

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक लचीली, शिक्षार्थी-अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाना था जिसमें सीखने की उपलब्धियों को पहचाना जा सके, संग्रहीत किया जा सके और व्यक्ति के पूरे जीवन भर उपयोग किया जा सके।
- यह क्रेडिट ट्रांसफर, कई प्रवेश और निकास विकल्पों को सक्षम बनाकर और विभिन्न संस्थानों और विषयों में सीखने की मान्यता प्रदान करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- यह डिजिलॉकर के माध्यम से सुलभ है, जो एक छात्र के स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित शैक्षिक रिकॉर्ड को एक ही मंच पर एकत्रित करता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भूगोल एवं भू-विज्ञान

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भारत में सिंचाई-आधारित कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

मुख्य बिन्दु:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- **परिचय:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015 में कृषि के लिये पानी की उपलब्धता बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने और टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था।
- **प्रकृति:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे एक कोर योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अधिकांश राज्यों के लिये केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु यह 90:10 है तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वित्त पोषण है।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को राज्य सिंचाई योजनाओं और ज़िला सिंचाई योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पिछले 10 वर्षों में पीएमकेएसवाई की उपलब्धियां

- **सिंचाई कवरेज का विस्तार:** पीएमकेएसवाई को 93,068.56 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-26 तक जारी रखा गया है।
- विभिन्न उपायों के माध्यम से 24.61 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर या विकसित किया गया है।
- **सिंचाई क्षमता में वृद्धि:** एचकेकेपी के हस्तक्षेपों ने लगभग 5.93 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन में मदद की है।

- भूमिगत जल संरक्षण उपायों से लगभग 88.55 हजार हेक्टेयर भूमि में वृद्धि हुई है।
- **सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना:** लगभग 110.92 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।
- प्रतिवर्ष लगभग 9.3 लाख किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **जल उपयोग दक्षता बढ़ाना:** स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई से पानी, उर्वरक, बिजली और श्रम की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों के अनुभव से पता चलता है कि पैदावार में 25-30% की वृद्धि हुई है।
  - पानी और अन्य संसाधनों के उपयोग में 50% की कमी आई है।
  - किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग ₹60,000-70,000 का मुनाफा होता है।
- **सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** जलसंभर संबंधी हस्तक्षेपों से मृदा स्वास्थ्य, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक स्थिरता में सुधार हुआ है।

MODEL RAS MAINS QUESTION:

Q. पिछले एक दशक (10 वर्षों) में भारतीय कृषि परिदृश्य को बदलने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की प्रमुख उपलब्धियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

आर्थिक घटनाक्रम

MECON लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा

चर्चा में क्यों?

- इस्पात मंत्रालय ने MECON लिमिटेड को उसकी पिछली श्रेणी-II से मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

MECON लिमिटेड

- MECON लिमिटेड भारत की अग्रणी, बहु-विषयक डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्श और ठेका देने वाली संस्था है, जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के रूप में हुई थी, जो शुरू में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (एचएसएल) के कैप्टिव डिजाइन विंग के रूप में कार्य करता था।
- **विकास:** बाद में इसका पुनर्गठन एक स्वतंत्र सार्वजनिक परामर्श फर्म के रूप में किया गया ताकि बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके ।

मिनीरत्न श्रेणी-I स्थिति:

- भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1997 मिनीरत्न योजना लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को दी जाने वाली एक प्रशासनिक श्रेणी है।
- इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष सरकारी वित्तीय सहायता के बिना संचालित होने वाली सार्वजनिक फर्मों को अधिक परिचालन स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियों का बेहतर प्रत्यायोजन और प्रतिस्पर्धी चपलता प्रदान करना है ।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

उद्देश्य:

- **उच्च प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई को नियमित नौकरशाही की लालफीताशाही से मुक्त करना, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।**
- **पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी गठजोड़ों पर त्वरित रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाना।**

अनिवार्य पात्रता मानदंड:

- **वित्तीय रिकॉर्ड:** **कंपनी को पिछले तीन लगातार वर्षों से निरंतर शुद्ध लाभ अर्जित करना आवश्यक था।**
- **लाभ सीमा:** **कंपनी का कर-पूर्व लाभ उन तीन लगातार वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना चाहिए था।**
- **सकारात्मक परिसंपत्ति बफर:** **संस्था को अनिवार्य रूप से सकारात्मक निवल संपत्ति बनाए रखनी चाहिए।**
- **शून्य डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड:** **संबंधित उद्यम ने भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के मूलधन या ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की होनी चाहिए।**
- **बजट का सहारा नहीं:** **सीपीएसई को स्वायत्त रूप से कार्य करना होगा, जिसका अर्थ है कि यह बजटीय सहायता या सरकारी वित्तीय गारंटी पर निर्भर नहीं रह सकता है।**
- **पुनर्गठित बोर्ड:** **किसी भी स्वायत्त शक्ति का प्रयोग करने से पहले बोर्ड का पुनर्गठन कम से कम तीन गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को शामिल करके किया जाना चाहिए ।**

MODEL QUESTION:

Q. मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) हेतु निर्धारित अनिवार्य पात्रता मानदंडों को रेखांकित कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु परिवर्तन बिंदु

चर्चा में क्यों?

- जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन के निर्णायक मोड़ एक प्रमुख बहस का विषय बनकर उभरे।

मुख्य बिन्दु:

जलवायु परिवर्तन के निर्णायक बिंदु

- जलवायु परिवर्तन का एक निर्णायक बिंदु पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण सीमा है, जिसके आगे एक छोटा सा अतिरिक्त परिवर्तन भी बड़े और संभावित रूप से अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को जन्म दे सकता है।
- एक बार जब टिपिंग पॉइंट पार हो जाता है, तो प्रभावित जलवायु प्रणाली में परिवर्तन जारी रह सकता है, भले ही मूल कारण कम हो जाए।
- यह सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्रों के माध्यम से काम करता है, जहां एक परिवर्तन दूसरे को सुदृढ़ करता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संभावित निर्णायक बिंदु

- **आर्कटिक सागर की बर्फ का पिघलना:** लगातार पिघलने से पृथ्वी की परावर्तकता (एल्बेडो) कम हो जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि होती है।
- **अमेज़न वर्षावन का क्षय:** बढ़ते तापमान, वनों की कटाई और घटती वर्षा के कारण अमेज़न के बड़े हिस्से सवाना में परिवर्तित हो सकते हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक कम हो जाएगा।

- **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन:** इस प्रमुख समुद्री धारा के कमजोर होने से यूरोप, अफ्रीका और एशिया भर में वर्षा के पैटर्न, कृषि और मौसम प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- **ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना:** बर्फ की चादर के तेजी से पिघलने से दीर्घकालिक वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में काफी योगदान हो सकता है।
- **प्रवाल भित्तियों का पतन:** समुद्र के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों का अपरिवर्तनीय विरंजन और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है।

MODEL RAS MAINS QUESTION:

Q. पृथ्वी के प्रमुख संभावित 'जलवायु निर्णायक बिंदुओं' (Climate Tipping Points) की पहचान करते हुए उनके वैश्विक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

हिमालयी रे-फिन मछली

चर्चा में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी संगनो कबीले ने लुप्तप्राय हिमालयी रे-फिन मछली (स्किज़ोथोरेक्स पेल्ज़ामी) के संरक्षण के लिए पूर्वी कामेंग जिले में स्थानांतरण अभियान शुरू किया है।

मुख्य बिन्दु:

हिमालयी रे-फिन मछली

- हिमालयी रे-फिन वाली मछली, जिसे आमतौर पर ट्रांसकैस्पियन मारिंका के नाम से जाना जाता है और स्थानीय रूप से नगारसिंग कहा जाता है, कार्प और मिनो परिवार से संबंधित एक विशेष मीठे पानी की प्रजाति है।

पर्यावास और वितरण:

- **भौगोलिक सीमा:** यह उप-हिमालयी और ट्रांसकैस्पियन क्षेत्रों की उच्च ऊंचाई वाली, तेज बहने वाली पर्वतीय धाराओं, नदियों और ठंडे पानी के झरनों में पाई जाती है।

- **सूक्ष्म-पर्यावास:** यह स्वच्छ, अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त, बर्फ से पोषित हिमनदीय धाराओं में पनपती है जो उच्च ऊंचाई पर स्थित होती हैं - जैसे कि पूर्वी हिमालय में लापाबुंग और रिचासो धाराएं, जो समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर स्थित हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसका दर्जा:** विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत।

MCQS

Q. हाल ही में सुर्खियों में रहा "स्किज़ोथोरेक्स पेल्ज़ामी" (Schizothorax pelzami) शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(A) पश्चिमी घाट में खोजी गई मेंढक की एक नई प्रजाति

(B) पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय मीठे पानी की मछली

(C) लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में उगने वाला एक औषधीय पौधा

(D) अंटार्कटिका के ग्लेशियरों के नीचे पाया गया एक प्राचीन जीवाणु